उत्तरांचल शासन राज्य पुनर्गठन विभाग संख्या– 105 / रा०पु० / **XXXVII** / 217 / 2006 देहरादून:दिनांक: ० २ मार्च, 2006

कार्यालय-ज्ञाप

सचिवालय अनुदेश 1982 के नियम—14 तथा नियम—15 में निहित प्राविधानों के अधीन राज्य पुनर्गठन विभाग के अन्तर्गत व्यवहृत होने वाले कार्यो / प्रकरणों के सम्पादन / निस्तारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री (विभागीय मंत्री) जी के अनुमोदन से निम्नवत् स्थाई आदेश निर्गत किये जाते हैं।

1- मा० मुख्यमंत्री (विभागीय मंत्री) जी के स्तर पर निस्तारण:-

1- समस्त नीति विषयक प्रकरण ।

2- ऐसे प्रकरण जिनमें मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा विचार/निर्णय होना है।

3— नियम एवं अधिनियम का निर्माण / संशोधन ।

4— ऐसे सभी प्रकरण जिनमें महामहिम श्री राज्यपाल की ओर से आदेश/निर्देश/अध्यादेश/अधिसूचना निर्गत की जानी हो ।

5— विधान सभा प्रश्न तथा विभिन्न नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनायें।

6- विभाग में नियुक्तियों के प्रकरण ।

7- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रकरण ।

8— ऐसे प्रकरण जिन्हें मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई हो ।

2- प्रमुख सचिव / सचिव स्तर पर निस्तारण:-

- 1— राज्य परामर्शीय सिमिति की बैठकों में मुख्य सिचव का प्रतिनिधित्व एवं लिये गये निर्णयों पर राज्य स्तरीय नीतिगत कार्यवाही / आदेश प्रदान करना ।
- 2- विभागीय बजट के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ ।
- 3— मा० उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/अभिकरण/लोकायुक्त /विविध आयोगों के प्रकरण में यथाआवश्यकता परामर्शीय विभागों से परामर्श प्राप्त कर विधिक कार्यवाही ।

4— भारत सरकार के आयोग / राज्य सरकार के आयोग एवं प्रदेश से बाहर व्यवहृत होने वाले पत्राचार ।

5— शासन के परामर्शी दात्री विभागों यथा कार्मिक, न्याय, वित्त को भेजे जाने वाले प्रस्ताव ।

6- लोक लेखा सम्परीक्षा / लेखा परीक्षा सम्बन्धी बिन्दुओं पर

कार्यवाही।

7- राज्य स्तर पर गठित विभिन्न समितियों का भेजी जाने वाली सूचनायें ।

8— विभागीय कार्मिकों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही ।

- 9— राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून/लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टि अंकन एवं अधीनस्थ कार्मिकों की वार्षिक पंजिकाओं का अन्तिमीकरण।
- 10— विभाग द्वारा संदर्भित प्रकरणों के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय तथा मार्गदर्शन ।

11- विभागीय बैठकों की अध्यक्षता एवं निर्णय ।

12— भारत सरकार द्वारा गठित राज्य परामर्शीय समिति एवं पुनर्गठन विषयक अन्य बैठकों में प्रतिभाग ।

13— आस्तियों एवं दायित्वों विभाजन हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की बैठकों में प्रतिभाग।

14— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत अपीलेट आथरिटी ।

15— सामान्य प्रकृति के अन्य विविध प्रकरण।

16— उत्तरांचल कार्य बंटवारा नियमावली—2003 एवं कार्य नियमावली में निहित प्राविधानानुसार कृत्यों का निवर्हन।

3- अपर सचिव स्तर पर निस्तारण:-

1— सचिवालय स्तर पर अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में यथा व्यवस्था प्रतिवेदक/समीक्षक प्राधिकारी के रूप में वार्षिक चरित्र पंजिकाओं का अंकन ।

2— उच्च स्तर से निस्तारित प्रकरणों में अनुमोदित पत्रावली पर पत्राचार ।

3- प्रमुख सचिव की अनुपस्थिति में उच्च स्तरीय नीतिगत विषयों से भिन्न अथवा उनके द्वारा यथा निर्दिष्ट विविध कार्य ।

4— राज्य परामर्शीय समिति की बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रमुख सचिव को सहयोग प्रदान करना ।

- 5— आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रमुख सचिव को सहयोग प्रदान करना।
- 6— विभिन्न विभागों से पुनर्गठन विषयक बिन्दुओं पर परामर्श।
- 7- पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण।
- 8- पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय पर वित्तीय नियंत्रण ।
- 9— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन।
- 10- न्यायालय वादों में प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार कार्यवाही।
- 11— राज्य परामर्शीय समिति की उत्तरांचल राज्य में आहूत बैठकों हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

(एन० एस० नपलच्याल) प्रमुख सचिव

संख्या— १°5 / रा०पु० / XXXVII / 217 / 2006, तद्दिनांक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :--

- 1— निजी सचिव, माननीय मुख्यमत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
- 2— निजी सचिव–मुख्य सचिव को मुख्यसचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
- 4- अपर सचिव, गोपन विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 5— राष्ट्रीय, विज्ञान सूचना केन्द्र, सचिवाल्य।
- 6— पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाईल ।

(हेमलता ढोंडियाल) अपर सचिव